

Question :- Examine the method of Judicial control over Public Administration.

Answer वर्तमान प्रजासामिक युग में तथा लोक कल्याण कारी रूपये में लोक प्रशासन का महत्व दिनोंदिन विकासान्वरप है। इसके बढ़ते हुए महत्व के कारण आज जीवन के हर क्षेत्र में लोक प्रशासन का किसी न किसी रूप में हम हस्तक्षेप आवश्यक पाते हैं। यहाँ-कहाँ ऐसा पाया जाता है, कि प्रशासन के हारा किसी भी कादा से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। अपने अतिक्रमित अधिकारों की रक्षा हेतु नागरिक न्यायालय का शरण लेते हैं।

अतः लोक प्रशासन के क्षेत्र में न्यायालय का काम नागरिक अधिकारों की रक्षा करना तथा प्रशासनीय अधिकारियों को उसकी सीमा में बनाए रखना न्यायालय होता है। न्यायपालिका की रचना संविधान में अत्याचार, अनियमितता, ग्रष्टाचार आदि दोषों का दूर करने के उद्देश्य से की गई है। जब कोई सरकारी अधिकारी नागरिकों के संविधानिक या मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो न्यायपालिका उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार न्यायपालिका का नियंत्रण प्रशासनीय कादों की वैधिकता निश्चित करता है। प्रशासनीय कादों पर न्यायिक नियंत्रण की धारणा विधि के शासन के सिहान्त से उद्भूत हुआ है। उचित न्यायिक नियंत्रण हेतु न्यायालय को कार्य कुशलता प्रशासन में विशिष्ट महत्व दरवता है। इस सबमें मौलिक न्यायपालिका को कहा जाता है:— "There is no better test of excellence of a government than the efficiency of its judicial system."

Ground of Judicial Control — न्यायपालिका का क्रतिपूर्व विशेष परिस्थितियों के आधार पर प्रशासन और नियंत्रण दरवता आवश्यक हो जाता है। Dr. J. A. White ने इन परिस्थितियों को 5 ब्रक्स का बनाया है।

(i) LACK OF JURISDICTION :→ व्यविधान के बारा

(i)

शायदी आम ईनाह के बारा या विधान मंडल के द्वारा कर्तव्य-२ पर विप्रेशन पास कर या कानून बनाकर प्रशासन के अधिकार को नियन्त्रित किये जाते हैं। अतः न्यायालय के द्वारा उसी द्वारा में इन्हें करता है जो विधासक ने कोई कार्य अपने अधिकार या अधिकार धोने से बाहर या बिना अधिकार के किया है।

(ii) Error of Law : यदि विधासकीय अधिकारी कानून की गणतन्त्र व्याख्या करता है और नागरिक पर उनका उत्तराधिकार लाभ देता है, जो कानून के अनुसार उचित नहीं है तब वारतन ने कानून की सीमा के बाहर है, तो इसे न्यायालिक मुद्दा कहा जाएगा। तो इस आधार पर न्यायपालिका की अरण ली जा सकती है।

(iii) Error of fact-finding : कर्तव्य-२ विधासन द्वारा गणतन्त्र व्याख्या पर कर्म उठा लिया जाता है। न्यायालय ऐसे गणतन्त्र उठे कर्मों पर नियंत्रण रखती है और तथ्य को दृष्टिपोन्ने में विधासन का जो व्यक्ति, या शाक्ता दोषी होता है उसे न्यायपालिका दृष्टिकोण करती है।

(iv) Abuse of Authority : यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने हेतु बदले की मावना से अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो इस आधार पर न्यायालय इन्हें फूर संबोधित अधिकारी को दृष्टिकोण सकता है।

(v) Error of Procedure : यदि किसी व्यक्ति या संस्था को भावद पहुँचाने हेतु विधासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन न करने पर भी न्यायिक हस्तक्षेप संभव है।

METHOD OF JUDICIAL CONTROL

विधासन पर न्यायिक नियंत्रण रखने के कई रूप रहे तरीके हैं। न्यायपालिका विधासन पर नियंत्रण रखने के लिए मुख्यमान: निम्न तरीकों का प्रयोग करती हैं।

(i) Judicial Review of Administrative action

Legal decision : विधासकीय कार्यों की समय-२ पर नियंत्रण करना न्यायालय का प्रमुख कार्य है।

यदि उनके कार्य या प्रशासनीय आज्ञाओं अधिकारों के विरुद्ध हैं तो वैसी परिस्थिति में न्यायालय उन्हें अवैधा-
निक घोषित कर सकता है। भारत और इंग्लैण्ड में इस
अधिकार का प्रयोग व्यापक रूप से होता है।

(II) Statutory Appeals :- न्यायालय का कठिन है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका ने सौंपी गई से-
र्टफिली शास्ति का विरोध करे। प्रशासनीय आज्ञाओं के विरुद्ध एवं निर्णयों के विरुद्ध न्यायालयों में अपील की जा सकती है और न्यायालय का काम आज्ञाओं की वैधता अवैधता देखना हो जाता है। पक्षावधिकारी अपनी आज्ञाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु न्यायालय से प्राप्तना कर सकते हैं।

(III) Taxation :- व्यवस्थापिका जिस कानून द्वारा पशा-
सक को कर लगाने की शास्ति प्रदान करती है, उसका संविधानिक आधार होना चाहिए। न्यायपालिका अब देखती है कि संसदीय स्वीकृति के बिना कार्यपालिका करारोपण न करे।

(IV) Suite against the government :- कुछ परिस्थितियों में नागरिकों को सरकार के विरुद्ध जनयोग लगाने का भी अधिकार प्रदान किया जाता है, परन्तु ऐसा किन परिस्थितियों में किया जायेगा, अब संसद नपा राज्य विधान मंडलों द्वारा नया किया जाता है।

(V) Suite against Public officials :- सामर्त्य प्रशासन-
निक अधिकारी अपने कार्यों हेतु न्यायालयों के प्रति उत्तर दायी है। प्रशासन से किसी प्रकार की शिकायत होने पर कोई भी नागरिक न्यायालय की भारण ले सकता है। भारतीय संविधान शब्दपत्र तथा राज्यपालों को न्यायिक कार्यवाची से उन्मुक्ति प्रदान करता है।

(VI) Extra ordinary Remedies :- भारतीय संविधान की द्वारा उद्देश्य में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की असाधारण दीतियों के अंतर्गत विशेष विवादों में आवश्यकतानुसार लेकर जारी करने का व्यापक रूप विकसित है अधिकार प्राप्त है। ये असाधारण दीतियों निम्नवत हैं :-

(V) stay order → (निषेद्धाइा) → यह कार्यपालिका के अधिकारियों को निली विशेष नार्थ से रोकने के लिए किया जाता है जबकि प्रतिषेध आदेश नामक अधिकारियों को निली विशेष नार्थ से रोकने के लिए जारी किया जाता है।

(i) Habeas Corpus → (बंदी प्रवधानकरण) → इस लेख का संबंध नजरबंदी की बैधानिकता जास्तने से होता है। Habeas Corpus का शाहिदक अर्थ (to produce the body of) शरीर को प्राप्त करना है। इस लेख के माध्यम से न्यायालय उन व्यक्ति या व्यक्ति को जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है, आदेश देता है कि उस व्यक्ति को सशारीर न्यायालय में उपस्थित करेंगा और न्यायालय बेदी बनाये जाने के आंचलिय पर विचार कर सके। L. D. White का कथन है "The effect of the writ in any case is to cause the person under detention to be brought before the cause for determination of the legality of his detention."

(ii) Mandamus (परमादेश) → इस लेख का शाहिदक अर्थ है "किसी को आड़ा देना"। यह उच्च न्यायालय द्वारा नोटे के न्यायालय व्यक्ति पर विगम की जारी किया जाया आदेश है। इस लेख के अनुसार सरकारी आदेशकारियों द्वारा विगमों को यह आड़ा दी जानी है कि वे उन कर्तव्यों का अवश्य पूरा करे जिन्हें उन्होंने भुला रखा हैं।

(iii) Prohibition (निषेद्धाइा) → यह लेख उच्च संघीय न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालय को जारी किया जाता है। इस लेख का उद्देश्य निचले न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकना है जो उसे कानून प्राप्त नहीं है। इसके द्वारा प्रशासन पर बहुत कम नियंत्रण रखा जाता है।

(iv) Certiorari → (उत्प्रेषण लेख) → इस लेख का शाहिदक अर्थ है "समाप्ति होना" (to be certified) या निश्चय होना (to be certain)। यह उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय को जारी किया जाया रक्त आदेश है जिसमें वह नीचे के न्यायालय को यह आड़ा देता है कि वह किसी विशेष मुकदमे से संबंध कागजात उच्च न्यायालय को भेज दे अर्थात् इसके द्वारा उच्चतर न्यायालय नियन न्यायालय के आभलेखों की समीक्षा करता है।

जारी

⑤ Quo Warranto (अधिकार घटक) → लैटिन भाषा

Quo Warranto का शाहिदक अर्थ "किस समिपता
जा आधिकार वारा" (Authoris warrantia or, Authoris) है। इस लोटव के बारा किसी व्यक्ति के किसी पद हेतु देवे
से कानूनी औचित्य की जांच की जा सकती है। यह
सरकारी अधिनियम पर न्यायिक निपत्रण देवने का
एक प्रत्यक्ष साधन है।

इस प्रकार न्यायिक निपत्रण के
विभिन्न तरीके और रूपों की विवेचना ले स्पष्ट होता है
कि न्यायिक निपत्रण प्रशासन को उसकी दीमा में
कार्य करने हेतु प्रेरित करता है।

Limitations on Judicial Control of Administration

आलोचकों का मत है कि न्यायिक निपत्रण का अधिक भाग में ज्योग प्रशासन के लिए उचित सिद्ध नहीं
होता बयोंकि इससे आवान की नियमितता और कुशल
संचालन बाधित हो जाता है। L.D. White के अनुसार

"At one extreme the vigour of judicial control
may paralyse effective administration." अतः
न्यायिक निपत्रण की गिरत सीमाएँ हैं।

① कुछ प्रशासनीय कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कार्य-
पालिका के हाताधिकार से बाहर देवा जाता है। ऐसे
प्रशासनीय कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती।
~~कार्यी~~

② जो प्रशासनीय कार्य न्यायपालिका के अधिकार द्वारा
मौद्दों हैं, उनपर न्यायालय अपनी ओर
से कोई कठम उठा सकता बयोंकि वह केवल पीड़ित
अपवा प्रभावित पक्ष की भारीता पर ही हस्तांतर कर
सकती है।

③ कुछ न्यायिक कार्यवाही बहुत व्यापक सम्बन्ध है, अतः
अधिकारी लोग इसका जाम नहीं उठा पाते हैं।

④ न्यायिक प्रक्रिया उत्तमी तथा मुँह होने के कारण
निर्णयों में व्यापक विलंब हो जाता है, फलतः लोग

ज्ञानालय की छाता और पाठों के दिवाली है। इस समय
में ज्ञानालय की बड़ी कमी है जो "Insufficient
Delayed at in sufficient capacity."

(3) साधारणतः ज्ञानालयों के ज्ञानप्रवाह लापता है, यद्यपि
ज्ञानप्रवाह के ज्ञानालय और ज्ञानप्रवाह नियंत्रण दोनों की विधियाँ
में नहीं लिपि हैं। इसी कारण ज्ञानप्रवाह के प्रबोधन
भागले भ्राताहानि, ज्ञानालयप्रबोधनों के पास चौप दिए
जाते हैं।

CONCLUSION → अस्तु निष्पत्तिः

कि प्रगालन पर ज्ञानप्रवाह नियंत्रण लोगों के द्वारा होके
नियंत्रित अनिवार्य रूपे लोप्तायाँ हैं। उपरोक्त वापर, वापर
के कारण ही ज्ञानालयों का ज्ञान अस्तित्व का
शाकार ज्ञानालय की मौजा है। अतिरिक्त जांची वायालोंपरा
अपात काल में इनकी ज्ञानप्रवाहिका के ज्ञानालय का
दुष्परिणाम जनता को गोगों पढ़े हैं। न्यायिक नियंत्रण
की स्टेट्टलन-वारिता पर सीमित अर्थ में कुछ अभियानों
का भी ध्वन्यान है। बास्तव में यह ब्रह्मानीय आदि
कारी ज्ञानप्रवाह और पक्षपात सीनु हैं जापे तो न्यायिक
और न्यायिक नियंत्रण एवं पर्यावरण की आवश्यकता नहीं है।

अंततः यह कहा जाता छोड़ा जाता है कि वर्तमान
संकरी में नियंत्रण विकासाभिल प्रज्ञालयीय दायित्वों और
परोक्ष स्टेट्टलन-वारी व्यक्तियों के कान एवं उन्हें सर्वानित
करने हेतु न्यायिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण अभिकावलनीय
है। इसी लक्ष्यके द्वारा तलतार की गोत्रि है जिसके मध्य
से प्रज्ञालयीय आधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सतकेन्द्र
स्टेट्टलन-वारिता से लियुव छोने का प्रयास करते हैं। यहाँ
L.D. White की उमित उस्तुत बहुत भावांगिक है कि-

"Officials always are aware that their acts
may be challenged in the court and that
under some circumstances they may be
liable for damages if they make a mistake"